मध्य प्रदेश में नागरौनी बांध

2576. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश मे ग्वालियर खण्ड की अनिवार्य आवश्यकताए पूरी करने के लिये चुनी गई सिन्ध नदी नागरौनी बाध परियोजना कब से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये उसके विचाराधीन है ,

(ख) उन्होने इस परियोजना के स्थल का हाल मे कब निरीक्षण किया था ,

(ग) यदि हा, तो क्या उन्होने वहा ऐसी कोई घोषणा की थी कि इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित तिथि से आरम्भ हो जायेगा, और

(घ) यदि हा, तो क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ हो गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) सिंध व्यपवर्तन वीयर स्कीम (चरण-1) की परियोजना रिपोर्ट अक्तूबर, 1966 में प्राप्त हुई थी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके इसकी तकनीकी जाच की जा रही है।

(ख) जी, हा। अप्रैल, 1965 में।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नही उठता।

चम्बल जलविद्युत् परियोजना

2577. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में चम्बल जल विद्युत् योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) इस परियोजना का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय किया जायेगा तथा इससे पानी और बिजली कितनी मात्रा में मिलेगी ,

(घ) पिछले कृषि वर्ष मे चम्बल नहर से कितने एकड भूमि मे सिंचाई हुई थी ; और

(ङ) पिछले एक वर्ष मे चम्बल से कितने वाट बिजली पैदा की गई तथा उसमे से ग्रामीण क्षेत्रो को कृषि, लघु उद्योगो तथा प्रकाश के लिये और नगरीय क्षेत्रो को क्रमश कितनी बिजली सप्लाई की गई थी ,

सिंचाई तथा विद्युत् मत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चम्बल बहुद्देश्यीय परियोजना पर 31 मार्च, 1967 तक 93 76 करोड रुपये व्यय किए गए है।

(ख) 1969–70

(ग) चम्बल बहुद्देश्यीय परियोजना पर कुल अनुमित व्यय 107 73 करोड रुपये का है। पूर्ण होने पर इस परियोजना से 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 230 मैगावाट पन-बिजली पैदा होगी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान मे 14 लाख एकड भूमि को सिंचाई की सुविधाए मिलेगी।

(घ) मध्य प्रदेश मे 61,000 एकड और राजस्थान मे 2,30,000 एकड।

(ङ) चम्बल से उत्पन्न की गई बिजली मध्य प्रदेश और राजस्थान के विडो को दी जाती है। इस लिए विभिन्न उपभोक्ताओ द्वारा खपत की गई बिजली का विभाजन उपलब्ध नही है।

Marketing of I.O.C. Oil Through Cooperative Societies

2578. **Shri Indrajit Gupta:**
Shri Vasudevan Nair:
Shri N C. Chatterjee:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corporation has refused to market the

bulk of its oil products through co-operatives societies which are prepared to do so;

(b) whether the Indian Oil Corporation is supplying to a private firm, Hindustan Organisers, four times the quota of oil supplied to all cooperative societies put together and at cheaper rates also; and

(c) if so, the reasons for giving preference to a private firm in comparison to the cooperative sector?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) No, Sir.

(b) The answer to the first part of the question is in the negative; and to the second part in the affirmative.

(c) The price charged to the Hindustan Organisers is in terms of an agreement and its basis has been explained in the 12th Report of the Committee on Public Undertakings (3rd Lok Sabha).

Working of Public Undertakings

2579. Shri Bedabrata Barua: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) what measures have been taken by Governmen. to avoid losses incurred by the Public Undertakings; and

(b) the amount of losses incurred by the public undertakings during the last 2 years?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The working of Public Sector Undertakings is being constantly reviewed and every effort is being made to seek improvement in performance by helping them to secure adequate orders for their products bringing down costs, etc.

(b) During 1965-66, out of 40 "Running" Enterprises, only 8 incurred losses, totalling Rs. 7.9 crores. In 1964-65, 5 Enterprises sustained a total loss of Rs. 2.4 crores.

Grid Net Work in Madhya Pradesh

2580. Shri G. S. Mishra: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any request from the Madhya Pradesh Electricity Board for additional funds is pending with the Centre;

(b) if so, the action being taken thereon; and

(c) what is the allocation of foreign exchange release made to the Madhya Pradesh Electricity Board for the procurement of imported stores required for early completion of 220 KV transmission lines under construction?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) A reques has been received recently from the Chief Minister of Madhya Pradesh for special allocation of Rs. 2 crores towards certain new schemes for electrification of pumps proposed to be undertaken by the Madhya Pradesh Electricity Board.

(b) This is under consideration at present.

(c) For the procurement of imported equipment pertaining to the 220 KV transmission system under construction in Madhya Pradesh, foreign exchange totalling Rs. 3.76 crores was released.

Housing Programme for Orissa

2581. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the amount given for housing programmes in Orissa under the Third Plan;

(b) the amount spent under the several heads of housing so far;

(c) the reasons for the shortfall in expenditure;

(d) the amount allotted to Orissa in 1966-67 and 1967-68; and

(e) the amount spent in 1966-67?